

## प्रेस विज्ञापित

14 दिसंबर, 2015

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, मीडिया प्रभारी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी ने आज प्रेसवार्ता में निम्नलिखित बयान जारी किया :-

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरकर लगभग 36 डॉलर प्रति बैरल हो गई हैं, जो कि 11 वर्ष पहले साल 2004 की कीमतों के बराबर है। परंतु मोदी सरकार पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों पर अनाप शनाप टैक्स लगाकर व्यापक मुनाफाखोरी में जुटी है।

साधारण जनमानस एक तरफ तो खाने पीने की आम वस्तुओं, जैसे कि दाल-खाने का तेल-सब्जी-आटा इत्यादि के दामों में भयंकर बढ़ोत्तरी से पीड़ित है, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार सर्विस टैक्स (14 प्रतिशत), स्वच्छ भारत टैक्स (0.50 प्रतिशत), स्किल डेवलपमेंट टैक्स लगाकर करों का अतिरिक्त बोझ लाद रही है। देश की जनता को राहत देने की बजाए मात्र पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स लगाकर भाजपा सरकार ने 2014-15 में 74,000 करोड़ रु. कमाए। साल 2015-16 में पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स के माध्यम से होने वाली आय का आंकड़ा मोदी सरकार ने 1,10,000 करोड़ रु. रखा है। इस प्रकार से जनता की भलाई के लक्ष्य को पूरा करने के लिए चुनी भाजपा सरकार देश की जनता की गाढ़ी कमाई का दोहन करने में लगी है।

26 मई, 2014 को जब श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तब कच्चे तेल की कीमत 108.05 डॉलर प्रति बैरल थी। आज यह घटकर लगभग 36 डॉलर प्रति बैरल रह गई है। कच्चे तेल से बनने वाले पेट्रोल की तेल रिफाईनरी कीमत आज मात्र 23.70 रु. प्रति लीटर है, जबकि पेट्रोल का बाजार भाव 60.48 रु. प्रति लीटर (दिल्ली में) है। यानि कि पेट्रोल की रिफाईनरी कीमत तो मात्र 23.70 रु. प्रति लीटर है, और मोदी सरकार का पेट्रोल की बिक्री से होने वाला मुनाफा 36.71 रु. प्रति लीटर है। इसी प्रकार से कच्चे तेल से बनने वाले डीजल की रिफाईनरी कीमत मात्र 24.67 रु. प्रति लीटर है और बाजार भाव 46.55 रु. प्रति लीटर है। यानि कि डीजल की रिफाईनरी कीमत तो मात्र 24.67 रु. प्रति लीटर है, और मोदी सरकार का डीजल की बिक्री से होने वाला मुनाफा 21.88 रु. प्रति लीटर है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि देश की तेल कंपनियां पहले एक बैरल तेल के लिए 6331 रु. लागत देती थीं, परंतु अब यह कम होकर मात्र 2726 रु. प्रति बैरल रह गई है। परंतु सारा मुनाफा सरकार स्वयं की जेब में टैक्स के माध्यम से डाल रही है बजाए आम जनमानस को राहत देने के। यह निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट है :-

## पेट्रोल

|  | जून 2014<br>(रु./लीटर ) | दिसंबर 2015<br>(रु./लीटर ) |
|--|-------------------------|----------------------------|
| लोगों के लिए खुदरा दर                                  | 71.46                   | 60.48                      |
| सरकार का मुनाफा<br>(टैक्स+कंपनी मार्जिन+डीलर<br>कमीशन) | 14.67                   | 36.71                      |

## डीज़ल

|  | जून 2014<br>(रु./लीटर ) | दिसंबर 2015<br>(रु./लीटर ) |
|--|-------------------------|----------------------------|
| लोगों के लिए खुदरा दर                                  | 57.28                   | 46.55                      |
| सरकार का मुनाफा<br>(टैक्स+कंपनी मार्जिन+डीलर<br>कमीशन) | 1.95                    | 21.88                      |

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के 125 करोड़ लोगों की ओर से पुरजोर मांग करती है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में अप्रत्याशित कमी का फायदा देश के लोगों को दें। देश की जनता पर भारी भरकम 1,10,000 करोड़ सालाना टैक्स से राहत दें और पेट्रोलियम पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का फायदा भारत के साधारण जनमानस को दें। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में कमी होते ही खाने पीने की वस्तुओं की कीमतें अपने आप कम हो जाएंगी। रेल का किराया भी कम हो जाएगा और बस तथा यातायात के अन्य साधनों का भी। इससे पूरे देश को व्यापक राहत मिलेगी। हम मांग करते हैं कि मोदी सरकार देश की जनता के प्रति अपने कर्तव्य को समझे तथा लोगों की आंख में धूल झोंकने की बजाए जनता से किए अपने वायदे पूरे करें और अपनी जिम्मेदारी पर खरा उतरें।